



OK

भारत का यजपत्र

The Gazette of India

प्राधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रतिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 1992/चैत्र 10, 1914

No. 220] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 1992/CHAITRA 10, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Filing is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आवेदन

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1992

का. आ. 250(अ)/18कक आई. डी. आर. ए./92 - भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विभाग) के आदेश सं. 320(अ)/18कक/आईडीप्रारए/79 मार्च 26 मई, 1979 द्वारा (जिसे इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) मेंससे अपोलो जिपर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता नामक संपूर्ण औद्योगिक उपकरण का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की द्वारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (क) के प्रधीन 25 मई, 1982 तक की, जिसमें यह नारीश भी मन्मिलित है, तीन वर्ष की प्रवधि

के लिए ग्रहण किया गया था और सचिव, बख्त और अन्य उच्चोग, औषधिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को उत्तर औषधिक उपक्रम का प्रबद्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय छोटे पर कि सोकल्हित में यह समर्चित है कि उत्तर आवाग तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 31 मार्च, 1992 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अधिक के लिए इसे जारी रखने के लए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे। [देखिए भारत सरकार के उचित मदालय] (आधिकारिक विकास विभाग) के प्राधेश

ਸ ਕਾ ਜਾ 246(ਅ)/18ਕ/ਪ੍ਰਾਈ ਦੀ ਆਰ ਏ /32, ਸਾਰੀਆਂ '5 ਮਈ, 1980

सं. का आ 822(अ)/18क्क/थाई डी आर ए/82, तारीख 24 नवम्बर 1982,

स का आ 385(अ)/18क/प्राइ डी आर ए/83, सारीख 31 मार्च, 1983,

सं का. घा 872(अ)/18कक्ष/प्राई डी घार ए/83, तारीख 30 नवम्बर, 1983,

संकाया 472(अ)/18फम/भार्ष वी आर ए /84, तारीख 28 जन, 1984,

सं का आ ९७६(अ) / १८कक/ग्राइ डी ग्रार ए /३४, तारीख २९ दिसम्बर, १९८४,

सं. का. भा २७५(अ)/१८पक/प्राई बी प्रार ए/८५, सारीख २९ मार्च, १९८५,

सं का. प्रा 146(अ)/18फ़र्म/पाई ही गार ए/86, तारीख 31 मार्च, 1986,

सं का आ 366(अ)/18क्क/प्राई ही प्रार ए /87. तारीख 30 मार्च, 1987.

ਸੰ. ਕਾ. ਸ਼ਾ. 326(ਅ)/18ਅ/ਪਾਈ ਝੀ ਪਾਰ ਏ /88, ਤਾਰੀਖ 10 ਮਾਰਚ 1987

सं का अ। 347(अ) / 18 अक्टूबर 1989, वारीख 31 मार्च, 1989

8. ११. ११. २७७(ख)। लोकसभा की विषय का इस परिवर्तन का अधिकार ।

¹¹ See *W.W. Mayo's (1913) Law of Task Assignment*, p. 121, which says, "The best way to get the best work from your workers is to let them do what they know best."

तक भी, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि में प्रभावी बना रहे

अब: कल्पाय, सरकार उद्धार (विकास और सान्तानम) भारतीयम, 1951 (195 ल 65) का धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक के माथ पठित धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रवर्तन यांत्रियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देता है कि उक्त भाइयो 31 मार्च, 1993 तक की, जिसमे यह तारीख भी सन्मिलित है, और प्रबंधि के लिए प्रधारी बना रखेगा।

[फा स 2/23/80 - नी यू एस]
एन आर कृष्णन, अपर मैटिक

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th March, 1992

S.O. 250(E)|18AA|IDRA|92 :—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 320(E)|18AA|IDRA|79, dated the 26th May, 1979 (hereinafter referred to as the said order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs. Apollo Zipper Company Private Limited, Calcutta was taken over under clause (a) of Sub-section (1) of Section 18AA of the Industries Development & Regulation Act, 1951 (65 of 1951) for a period of three years upto and inclusive of the 25th May, 1982 and the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, was authorised to take over the management of the said Industrial Undertaking ;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1992 [Vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development)].

Nos. S.O. 246(E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th May, 1982,

S.O. 832(E)|18AA|IDRA|82, dated the 24th November, 1982,

S.O. 385(E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st March, 1983,

S.O. 872(E)|18AA|IDRA|83, dated the 30th November, 1983,

S.O. 472(E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th June, 1984,

S.O. 975(E)|18AA|IDRA|84, dated the 29th December, 1984,

S.O. 275(E)|18AA|IDRA|85, dated the 29th March, 1985,

S.O. 146(E)|18AA|IDRA|86, dated the 31st March, 1986,

S.O. 266(E)|18AA|IDRA|87, dated the 30th March, 1987,

S.O. 326(E)|18AA|IDRA|88, dated the 30th March, 1988,

S.O. 247(E)|18AA|IDRA|89, dated the 31st March, 1989,

S.O. 277(E)|18AA|IDRA|90, dated the 30th March, 1990, and

S.O. 214(E)|18AA|IDRA|91, dated the 26th March, 1991,

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a period upto and inclusive of 31st March, 1993;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2), of Section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Orders shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1993.

[F. NO. 2(23)|80-CUS]

N. R. KRISHNAN, Addl. Secy,